- 19th Year
- Issue: 301
- 13.03.2026 (FRIDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

ईरान को समझाने में जयशंकर रहे सफल, खाड़ी में भारतीयों की सुरक्षा के लिए मोदी लगा रहे पूरा जोर

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता): भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हाल के दिनों में ईरान के विदेश मंत्री के साथ तीन दौर की बातचीत की है। इन वार्ताओं में मुज़्य रूप से समुद्री जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं के बारे में अभी अधिक विस्तार से बताना सही नहीं है ज़्योंकि क्षेत्र की स्थिति अभी संवेदनशील और बदलती हुई है। उल्लेखनीय है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के कारण तनाव बढ गया है और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है।

प्रेस वार्ता में प्रवक्ता ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी के प्रयासों की जानकारी भी दी। उनके अनुसार लगभग नौ हजार भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं। इनमें विद्यार्थी, नाविक, व्यापारी, पेशेवर लोग और कुछ तीर्थ यात्री भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई भारतीय नागरिक, विशेष रूप से विद्यार्थी, पहले ही देश लौट चुके हैं। तेहरान में रह रहे कई भारतीयों को सुरक्षित स्थानों और अन्य शहरों में स्थानांतरित किया गया है। विदेश मंत्रालय उन भारतीय नागरिकों की भी सहायता कर रहा है जो स्थल सीमा मार्ग से अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से भारत लौटना चाहते हैं। मंत्रालय उन्हें वीजा उपलज़्ध कराने और सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है। प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि जो लोग जमीनी सीमा के माध्यम से ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं, वह दूतावास द्वारा जारी परामर्श का पालन अवश्य करें।

प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि पांच मार्च को भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव ने ईरान के दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है और बिना जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिन शोक पुस्तिका रखी गयी थी भारत ने उसी दिन उस पर हस्ताक्षर किये थे। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस तरह के आरोप लगाये गये कि भारत ने शोक व्यक्त करने में कई दिन लिये।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव का भारत ने सह प्रायोजन किया है। इस प्रस्ताव को एक सौ पैंतीस देशों का समर्थन प्राप्त है। प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रस्ताव भारत के कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय की बड़ी संज़्या रहती है और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सहयोग के विषय में प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत अपने पड़ोसी देशों को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से डीजल आपूर्ति का अनुरोध किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से बांग्लादेश को डीजल निर्यात जारी है, परंतु किसी भी निर्णय से पहले भारत की परिष्करण क्षमता, घरेलू आवश्यकता और उपलज़्धता को ध्यान में रखा जायेगा। इसी प्रकार श्रीलंका और मालदीव सहित कई अन्य देशों से भी ऊर्जा सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरान ने बीस फरवरी को अपने तीन जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर ठहरने की अनुमति मांगी थी, जिसे एक मार्च को स्वीकृति दे दी गयी। इनमें से एक जहाज आईआरआईएस लावन चार मार्च को कोच्चि पहुंचा और उसका दल फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में है। इसके अलावा, पाकिस्तान द्वारा भारत कनाडा यूरेनियम समझौते पर की गयी टिप्पणी को भारत ने सज़्ती से खारिज किया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि परमाणु अप्रसार के मामले में भारत का रिकॉर्ड निष्कलंक है और इसे पूरी दुनिया मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि जिस देश का गुप्त परमाणु प्रसार का इतिहास रहा है, उसे इस विषय पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की विश्वसनीयता शून्य है और वह अज़्सर अपने कृत्यों से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगाता है।उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र के कई नेताओं से बातचीत की है। इन वार्ताओं में उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से शीघ्र शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और जनहानि रोकने के महत्व को भी रेखांकित किया।नेपाल के संदर्भ में प्रवक्ता ने बताया कि वहां चुनावों के सफल समापन का भारत ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वतंत्र दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने और वरिष्ठ नेता बालेन शाह से फोन पर बातचीत कर उन्हें जीत की बधाई दी और नेपाल के साथ साझी प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी।देखा जाये तो विदेश मंत्रालय की आज की प्रेस वार्ता ने स्पष्ट किया कि वैश्विक संघर्षों और अनिश्चितताओं के दौर में भारत की विदेश नीति संतुलन, जिज़्मेदारी और सक्रिय कूटनीति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और शांति की वकालत जैसे कदम यह दर्शाते हैं कि भारत विश्व मंच पर एक जिज़्मेदार और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। आइये देखते हैं प्रवक्ता की ओर से बताई गयी बड़ी बातें।

यूएस-ईरान युद्ध पर राहुल की चेतावनी, बोले-ये तो शुरुआत है, असली दर्द बाकी है

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता): लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति सीधे तौर पर प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की उपलज़्धता को लेकर चिंता पहले से ही फैल रही है और संघर्ष बढ़ने पर यह और भी गंभीर हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा को किसी भी देश के लिए मूलभूत बताते हुए गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि भारत को अमेरिका को इस बात पर प्रभाव डालने की अनुमति ज़्यों देनी चाहिए कि वह गैस कहां से खरीदे।राहुल गांधी ने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का 20त्न प्रवाह होता है, बंद कर दिया

गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए, ज़्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। रेस्तरां बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर व्यापक दहशत फैली हुई है... यह तो बस शुरुआत है। गांधी ने आगे कहा कि हर राष्ट्र की नींव उसकी ऊर्जा सुरक्षा है। अमेरिका को यह तय करने देना कि हम किससे तेल खरीदें, किससे गैस खरीदें और ज़्या हम रूस से तेल खरीद सकते हैं या नहीं...विभिन्न तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमारे संबंध हम खुद तय कर सकते हैं। यही सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को, किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति को, हमें रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने या यह तय करने की अनुमति ज़्यों देगा कि हमारे संबंध किसके साथ हों। राहुल गांधी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर तंज कतसे हुए कहा कि मैंने पहेली सुलझा ली है और पहेली समझौते से जुड़ी है। हमारे सामने यहां एक सज्जन बैठे हैं जो तेल मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वे श्री एपस्टीन के मित्र हैं।

एलपीजी पर विपक्ष का हंगामा, कंगना रनौत बोली-ये जनता को गुमराह करने की साजिश

नयी दिल्ली१२/०३ (संवाददाता): भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित एलपीजी संकट से देश को उसी तरह निकालेंगे जैसे उन्होंने कोविड महामारी के दौरान निकाला था। रनौत ने एलपीजी सिलेंडर संकट पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। कंगना रनौत ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देख रही है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में हर दिन नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। एलपीजी की स्थिति को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया है, लेकिन वे (विपक्ष) दहशत फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए यह (विरोध प्रदर्शन) कर रहे हैं। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखना चाहिए, जो कोविड महामारी के दौरान की तरह ही नेतृत्व करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को संसद परिसर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की देशव्यापी कमी की

खबरों के विरोध में अपना प्रदर्शन जारी रखा। भारत गठबंधन के नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा की मांग की है। एलपीजी की कमी का संकट देश के कई हिस्सों में भी व्याप्त है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी की खबरों पर चर्चा करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि संसद जनता को आश्वस्त करने और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का मंच है।ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती हैं... कुछ रेस्तरां ने कहा है कि उनके पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, वे चाय तो दे सकते हैं, लेकिन डोसा नहीं।

२०० सांसदों ने सीईसी को हटाने वाले नोटिस पर किए दस्तखत

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता): विपक्ष के 200 से अधिक सांसदों ने मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन पर पक्षपातपूर्ण आचरण और सज़ाधारी दल की मदद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह नोटिस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसे जल्द ही संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा के कुल 130 सांसदों और राज्यसभा के 63 सांसदों ने मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार, नोटिस शुक्रवार को कम से कम एक सदन में पेश किए जाने की संभावना है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस सदन में। इस बीच, विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने में काफी उत्साह दिखाया है और गुरुवार को भी कई सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए, जबकि आवश्यक संज़्या पहले ही पूरी हो चुकी थी। नियमों के अनुसार,

लोकसभा में मुज़्य आयुक्त को हटाने की मांग वाले नोटिस पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, जबकि राज्यसभा में आवश्यक संज़्या 50 है। सूत्रों के अनुसार, अखिल इंडिया गठबंधन (ऑल इंडिया ज़्लॉक) के दलों के सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप), जो अब आधिकारिक तौर पर गठबंधन का हिस्सा नहीं है, के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। मुज़्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए पहली बार नोटिस जारी किया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, नोटिस में मुज़्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सात आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना शामिल हैं। विपक्षी दलों ने मुज़्य चुनाव आयुक्त पर कई मौकों पर सज़ारूढ़ भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है, खासकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में, जिसका उद्देश्य केंद्र में पार्टी को लाभ पहुंचाना है।

पश्चिम बंगाल में मुज़्य चुनाव आयुक्त (सीआईआर) के संचालन को लेकर विशेष चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो और मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वैध मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है।

अमस चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज, हिमंता बोले-पवन खेड़ा का अंतिम संबोधन जेल में होगा

गुवाहाटी १२/०३ (संवाददाता): अमस में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपो पर मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए असम में किसी उग्रवादी संगठन से संपर्क करने की कोशिश करने के आरोप में पवन खेड़ा के नाम पर तीन-चार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो जेल कौन जाएगा? यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा का अंतिम संबोधन असम की जेल में ही होगा. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार द्वारा महिलाओं को विज़ीय सहायता वितरण सहित अंतिम समय में उठाए गए कदम आगामी विधानसभा चुनावों में असम में भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) को सज़ा में वापस लाने में मदद नहीं करेंगे। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और संचार अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मुज़्य रूप से मुज़्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों के हितों के लिए काम करती है।गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, खेरा ने दावा किया कि सरमा ने 2015 में भाजपा में शामिल होने से पहले ढाका में एक मौलवी से मुलाकात की थी। खेड़ा ने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे इसका खंडन करें। उन्होंने उस मौलवी की सलाह पर भाजपा में शामिल हुए। इस आरोप पर मुज़्यमंत्री या भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खेड़ा ने कहा कि सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद 2016 के असम विधानसभा चुनावों में पार्टी को पहली जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में अगली सरकार बनाएंगे और जिसे उन्होंने नया असम मॉडल बताया, उसे लागू करेंगे। तुलना करते हुए, खेड़ा ने कहा कि कुछ छात्र पूरे साल पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू करते हैं।

पश्चिम बंगाल बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित? एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता): भारत भर में लापता बच्चों की बढ़ती संज़्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम लापता बच्चे रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच कुल 33,577 बच्चे लापता हुए। हालांकि अधिकारियों ने इनमें से कई बच्चों का पता लगा लिया है, फिर भी 7,777 बच्चे लापता हैं, जो इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है। देशभर में बच्चों के लापता होने के आंकड़े चिंताजनक हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1

जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में कुल 33,577 बच्चे गायब हुए। इनमें से 7,777 बच्चे अब तक नहीं मिले।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा 19,145 बच्चे पश्चिम बंगाल में लापता हुए। इनमें से 15,465 बच्चों को ढूंढ लिया गया, जबकि 3,680 बच्चे अब भी नहीं मिले। मध्यप्रदेश में 4.256 बच्चे लापता हुए। इनमें से 1,059 बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया। बच्चों के लापज़ा होने के मामलों में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हरियाणा में 2209 बच्चे लापता हुए, लेकिन इनमें से 353 का कोई सुराग नहीं लग पाया। हरियाणा में लापता बच्चों की संज़्या पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ से कई गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लापता बच्चों की संज़्या सबसे अधिक रही, इस अवधि के दौरान 19,145 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 15,465 बच्चों का पता लगाया जा चुका है, जबकि 3,680 बच्चे अभी भी लापता हैं।

केस 1 सहेली के घर गई, फिर नहीं लौटी अज़्बाला की 14 वर्षीय लड़की 8 जनवरी को सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें वह जाते दिखी, पर आगे

केस 2 नाराज होकर घर से निकली, अब तक लापता- अज़्बाला कैंट में 5 फरवरी को लड़की परिवार से नाराजा होकर घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी का केस है।

पिता शहर में पर्चे बांटकर लोगों से बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंकड़े लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर करते हैं। अधिकारियों ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करने का आग्रह करना जारी रखा है।

विविध समाचार

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस, अमित शाह ने विपक्ष को धोया

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता):लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर गरमागरम बहस जारी रही। मंगलवार को हुई बहस के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने, माइक्रोफोन बंद किए जाने, विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति न दिए जाने और सामूहिक निलंबन जैसे प्रमुख मुद्दों पर शिकायत दर्ज की थी। इस बीच, राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रही। वहीं, मुज़्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस के लिए आवश्यक हस्ताक्षर ले लिये गए हैं और अगले एक-दो दिन में संसद के दोनों सदनों में इसे दिये जाने की तैयारी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

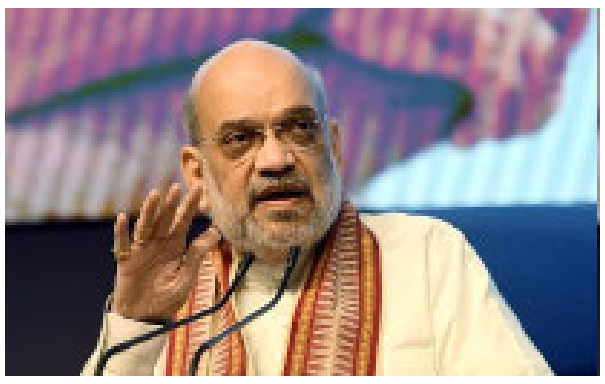

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव लाया जाना अफसोसनाक घटना है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई। उन्होंने कहा कि पहले जो तीन बार प्रस्ताव आया था, वो तब आया जब कांग्रेस पार्टी सज़ा में थी, लेकिन हम कभी नहीं लाए। तीनों बार ये परंपरा रही कि जब स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होगी तब इस स्थान पर स्पीकर साहब स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन ओम बिरला जी एकमात्र स्पीकर ऐसे हैं, जिन्होंने मोरल ग्राउंड पर जब से इन्होंने उन्हें नामित किया, तब से वो नहीं आए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सदन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाता और तंज कसते हुए कहा कि '' फोमो (फियर ऑफ मिसिंग आउट) गांधी को सुर्खियों से हट जाने का डर लगता है''।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ ''बांध'' दिये हैं, जिससे उन्हें सज़ारूढ़ दल की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश में रसोई गैस एलपीजी की कथित किल्लत मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जनता कितना बर्दाश्त करेगी? लोकसभा सदस्य ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि सदन में उन्हें बोलने से कई बार रोका गया है और देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को सदन में बोलने नहीं दिया गया। वहीं, सदन में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने संसदीय प्रणाली पर 'कॉल एंड शकधर' की एक किताब को उद्धृत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रहित के मुद्दों पर बोलते समय ध्यानपूर्वक शज़्दों का चयन करना चाहिए और विदेशी धरती पर दलीय राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया धोखाधड़ी है और इसे विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतने के लिए चलाया जा रहा है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खरगे ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सभी चुनावी राज्यों में चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2026-27 के बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। भाजपा के बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि सरकार ने सूरत और कुरनूल के बीच नया ग्रीन एज़्सप्रेस हाईवे बनाने का निर्णय लिया है, जिससे दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी लगभग 320 किलोमीटर कम हो जाएगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि इस राजमार्ग के निर्माण के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय भी घटकर 12 घंटे से कम हो जाएगा। राज्यसभा में भाजपा के बाबू राम निषाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे में हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर क्षोभ व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा आने वाले समय में कोई और राज्य इसकी पुनरावृज़ि कर सकता है।

केरल अब कहलाएगा केरलम, नरेंद्र मोदी बोले- एनडीए सरकार ने सालों पुरानी मांग पूरी की

नयी दिल्ली १२/०३ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम रखने की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य को अब उसका उचित नाम मिल गया है। केरल में अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मछुआरा समुदाय की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब मैं आप सबके बीच खड़ा हूं, तो पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। मेरे मलयाली भाइयों और बहनों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। आप सभी वर्षों से केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मांग कर रहे थे। केंद्र में हमारी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मैं आप सबके चेहरों पर खुशी देख सकता हूं। इस खूबसूरत राज्य को मलयाली संस्कृति के अनुसार उसका उचित नाम मिल गया है। 24 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के

प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केरल विधानसभा ने जून 2024 में नाम परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। अखिल केरल धीवर सभा के कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। अखिल केरल धीवर सभा अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। यह संगठन मछुआरा समुदाय के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। मैं केरलम के सभी मछुआरों और अखिल केरल धीवर सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं। यह उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन मेरे लिए जनता भगवान के समान है और मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं।उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं केरल आया, तो मैंने अखिल केरल धीवर सभा के सदस्यों से बातचीत की। अखिल केरल धीवर सभा ने जीवन और रोजगार, तथा प्रगति और प्रकृति के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप भारतीय दर्शन और विचार को जीते हैं। दुनिया जल, नदियों और समुद्रों को संसाधन मानती है। धीवर समुदाय महासागरों को अपनी %अज़्मा% (मां) मानता है। एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मछुआरा समुदाय की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दशकों तक मछुआरा समुदाय की उपेक्षा की है। लेकिन अब एनडीए सरकार प्रगति कर रही है और उन्हें असीमित क्षमताओं तक पहुंचा रही है।

कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी, गैस संकट और महंगाई पर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल

कोलकाता १२/०३ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में रसोई गैस और वाहन गैस की कमी को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और इसी बीच मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है।

मौजूद जानकारी के अनुसार यह मार्च सोमवार को कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर एस्प्लानेड के डोरिना क्रॉसिंग तक निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे।बता दें कि इस मार्च का उद्देश्य रसोई गैस और वाहन गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ विरोध दर्ज कराना बताया जा रहा है। पार्टी की ओर से जारी पोस्टर में कहा गया है कि आम लोगों को गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और आपूर्ति से जुड़े फैसलों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है। राज्य सरकार के अनुसार कुछ ही दिनों में सिलेंडर बुकिंग की संज़्या दो लाख से बढ़कर करीब छह लाख तक पहुंच गई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की है। राज्य की विज़ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद केंद्र ने पर्याप्त तैयारी नहीं की।उन्होंने कहा कि होरमुज जलडमरूमध्य से होकर भारत के रसोई गैस आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है और यह जानकारी पहले से सार्वजनिक थी। इसके बावजूद वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था या रणनीतिक भंडार बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में राज्य के अधिकारियों और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपात बैठक की थी। इस बैठक में राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं।बताया जा रहा है कि मुज़्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की रिफाइनरियों में तैयार होने वाली गैस की आपूर्ति फिलहाल राज्य के बाहर भेजने से रोकी जाए, ताकि स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि सज़ारूढ़ दल कृत्रिम संकट पैदा कर रहा है और गैस वितरण व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है।इसके जवाब में राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता को देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है और इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।बता दें कि गैस संकट के कारण कई जगहों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। वाहन गैस भरवाने के लिए कई ऑटो चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों ने बाजार में महंगे दाम पर सिलेंडर बिकने की शिकायत भी की है।मौजूद जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई हैं, जहां एक सिलेंडर की कीमत करीब ढाई हजार रुपये तक वसूली जा रही है। वहीं कई सरकारी अस्पतालों को मरीजों के भोजन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी सिलेंडरों का सहारा लेना पड़ा है। कुछ अस्पतालों में गैस की कमी की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं यदि लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इसका असर आम लोगों के दैनिक जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

कांग्रेस में एकता नहीं, अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव गिरने पर गिरिराज सिंह का तंज

१२/०३ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को लोकसभा द्वारा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पार्टी के भीतर एकता की कमी का आरोप लगाया। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने गृह मंत्री के जवाब के बाद मोहज़्मद जावेद से बोलने को कहा और बताया कि वे तभी बोल सकते हैं जब कांग्रेस सदस्य अपनी सीटों पर बैठ

जाएं। विपक्षी सदस्यों के जोरदार नारेबाजी के बीच, जगदंबिका पाल ने ध्वनि मत का आह्वान किया और कहा कि प्रस्ताव खारिज हो गया है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग (कांग्रेस) देश और लोकतंत्र के दुश्मन हैं। ये लोग लोकसभा में गरीबों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग देश में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। इनमें मतदान करने का साहस नहीं था ज़्योंकि इनमें एकता नहीं थी। आज अध्यक्ष ओम बिरला सदन में अध्यक्ष के रूप में लौटे और उन्होंने दोहराया कि वे निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद के निचले सदन के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह मंत्री हो या विपक्षी सांसद, नियमों के अनुसार बोलने का अधिकार है।

इस बीच, गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को दोहराते हुए कहा कि देश एलपीजी की कमी से उसी तरह निपट लेगा, जैसे उसने कोविड-19 महामारी के दौरान निपटा था। सिंह ने कहा कि हमने महामारी के दौरान सफलतापूर्वक काम किया। हम इससे भी निपट लेंगे।

बस्तर की धरती से उखड़ने वाली हैं नज़सलियों की जड़ें! विदा होगा गन और ग्रेनेड का दौर, डिप्टी सीएम का बड़ा एलान

बस्तर १२/०३ (संवाददाता): छज़ीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल से सशस्त्र नज़सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए एक निर्णायक समयसीमा (ष्ठद्गड्डस्रद्यद्बठ्ठद्ग) निर्धारित की है। मंगलवार को विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उपमुज़्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि राज्य से 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नज़सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके एक साल बाद, यानी 31 मार्च 2027 तक बस्तर में तैनात अधिकांश केंद्रीय बलों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

शर्मा ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जब 31 मार्च 2026 को सशस्त्र नज़सलवाद के समापन की तिथि तय की गई, तब यह भी निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च 2027 तक यहां तैनात केंद्रीय बलों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुछ बल उससे पहले भी वापस जा सकते हैं। बैठकों में इस बात पर सहमति बनी है कि 31 मार्च 2027 को हम एक निश्चित समय सीमा मानकर चलें, हालांकि इसमें थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। उन्होंने बताया कि विज़ीय वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस विभाग के मुज़्य बजट में कुल 7,721.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शर्मा ने बताया कि पुनर्वास करने वाले वामपंथी उग्रवादी नज़सली कैडर के पुनर्वास के लिए केंद्र की पुनर्वास नीति के तहत सावधि जमा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नज़सल प्रभावित जिलों में 15 नए थानों की स्थापना के लिए 975 नए पद सृजित किए जाएंगे।

उपमुज़्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही आठ पुलिस चौकियों को थानों में उन्नत करने के लिए 337 नए पद और कम बल स्वीकृत वाले 21 थानों में अतिरिक्त बल वृद्धि के लिए 870 नए पदों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 16 जेलों में 'प्रिजन कॉलिंग सिस्टम' स्थापित करने के लिए 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से वॉयस या वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे। शर्मा ने कहा कि इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुज़्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हर कोई चाहता है कि नज़सलवाद समाप्त हो और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक नज़सलवाद समाप्त हो जाएगा।

बघेल ने कहा, 31 मार्च में अब केवल 21 दिन शेष हैं। हमें उज़्मीद है कि इसके बाद अर्धसैनिक बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।卐 उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नज़सलवाद के समाप्त होने के बाद 31 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका जश्न मनाया जाना चाहिए और बस्तर के विकास का लाभ मुज़्य रूप से स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए।

बघेल ने चर्चा के बाद कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। कटौती प्रस्ताव बजट में पेश की गई अनुदान मांगों में से किसी विशेष मांग की राशि को कम करने के लिए लाया जाने वाला एक विधायी प्रक्रिया है। प्रस्ताव के विरोध में 37 और पक्ष में 24 मत पड़े, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके बाद सदन ने शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी।

कर्नाटक में मचा हड़कंप, पुलिस ऑफिस में रंगीनमिजाजी का वीडियो वायरल

बेंगलुरु १२/०३ (संवाददाता):: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए ष्ठत्रक्क रैंक के वरिष्ठ आईपीएस (ढ्ढक्कस्) अधिकारी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक आपज़िजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है, जिसमें कथित तौर पर अधिकारी को अपने सरकारी कार्यालय के भीतर विभिन्न महिलाओं के साथ आपज़िजनक स्थिति में देखा गया था। यह फैसला ष्ठत्रक्क रैंक के अधिकारी के सरकारी ऑफिस में कथित व्यवहार को लेकर बढ़ते विवाद और लोगों के गुस्से के बीच आया। यह विवाद मुज़्यमंत्री सिद्धारमैया के ऑफिस तक पहुंच गया, जिन्होंने सोमवार को संबंधित विभाग से जानकारी ली।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती है टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी

चीन में एक ऐसी लाइब्रेरी है, जिसे देखने के बाद आपकी निगाहें उसी पर टिकी रहेंगी। आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती इस लाइब्रेरी का नाम है 'टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी' जिसकी खूबसूरती देख आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, कि ये एक लाइब्रेरी है। यहां कुछ लोग तो सिर्फ फोटो के लिए ही इस लाइब्रेरी का रूख करते हैं। बता दें, इस लाइब्रेरी को चीन के 'नेशनल डे' को आम जनता के लिए खोला गया है। 37, 000 स्कायर फीट तक फैली टियांजिन बिनहाइ लाइब्रेरी में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस लाइब्रेरी की उंचाई करीब पांच मंजिल के बराबर बनी हुई है। यहां पर पढ़ने के लिए हर जॉनर करीब 12 लाख से भी ज्यादा किताबें मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी में लगभग हर जॉनर में 12 लाख किताबें हैं। इस लाइब्रेरी को बिनहाई कल्चरल सेंटर में खोला गया है, जिसे डच कंपनी एमवीआरडीवी ने डिजाइन किया है। इस खूबसूरत चीन की लाइब्रेरी में एक बेहद ही यूनिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी आखं बनी हुई है,

इस आंख के डिजाइन पर अंदर होने वाली चीजों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है।

- इस लाइब्रेरी में तकरीबन हर जॉनर की 12 लाख किताबें हैं.
- शहर के बिनहाइ कल्चरल सेंटर में खुले इस लाइब्रेरी को डच कंपनी एमवीआरडीवी ने डिजाइन किया है.
- इस लाइब्रेरी में सर्विस स्पेस, बुक स्टोरेज, आर्काइव, कंप्यूटर रूम, ऑडियो रूम, ऑडिटोरियम, लाउंज, मीटिंग रूम, ऑफिस और रीडिंग स्पेस भी हैं.
- इन किताबों और लाइब्रेरी के बीच एक बहुत बड़ी आंख भी बनी हुई है. – इस आंख पर अंदर होने वाली चीजों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है.
- इसे चीन के नेशनल डे पर आम जनता के लिए खोल दिया गया.

ये है धरती का सबसे पुराना पेड़

महाभारत से पहले का है इसका इतिहास

इस दुनिया में एक नही बल्कि कई सारी गजब की जगह और चीज मौजूद है जो लोगों को हैरान कर देती है। पेड़ हम इंसानों के लिए कितने जरूरी है यह बात तो सभी जानते है। अगर इस धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान का जीना संभव नहीं है। जब भी पुराने पेड़ो की बात निकलती है तो अक्सर लोगों को बरगद का पेड़ याद आता है। लोग यही कहते हैं की बरगद के पेड़ सालों साल जीते हैं और यह सबसे पुराने होते है। लेकिन आज हम आपको इस दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में बताते है जो हजारों साल पुराना है। दुनिया के इस सबसे पुराने पेड़ की बात करें तो यह चिली में पाया गया है, जो लगभग 5000 साल से ज्यादा पुराना है। साइप्रस ट्री के नाम से पहचाने जाने वाला यह पेड़ ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने इसलिए नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह धरती पर मौजूद सबसे पुराना पेड़ है।

कितने साल का है पेड़

इस पेड़ की उम्र की बात करें तो यह 5484 साल का है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह 6000 साल से ज्यादा पुराना है। यह 13 फिट चौड़ा और 28 मीटर लंबा है। इस पर लगातार शोध चल रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसने जलवायु परिवर्तन के साथ खुद को किस तरह से अनुकूल रखा।

हासिल किए ये खिताब

ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ चिली के एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में मौजूद है। जिस कैलिफोर्निया के पाइन पेड़ को हराकर सबसे पुराना पेड़ होने का खिताब अपने नाम किया है। धरती के इस सबसे पुराने पेड़ में लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अक्सर लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं।

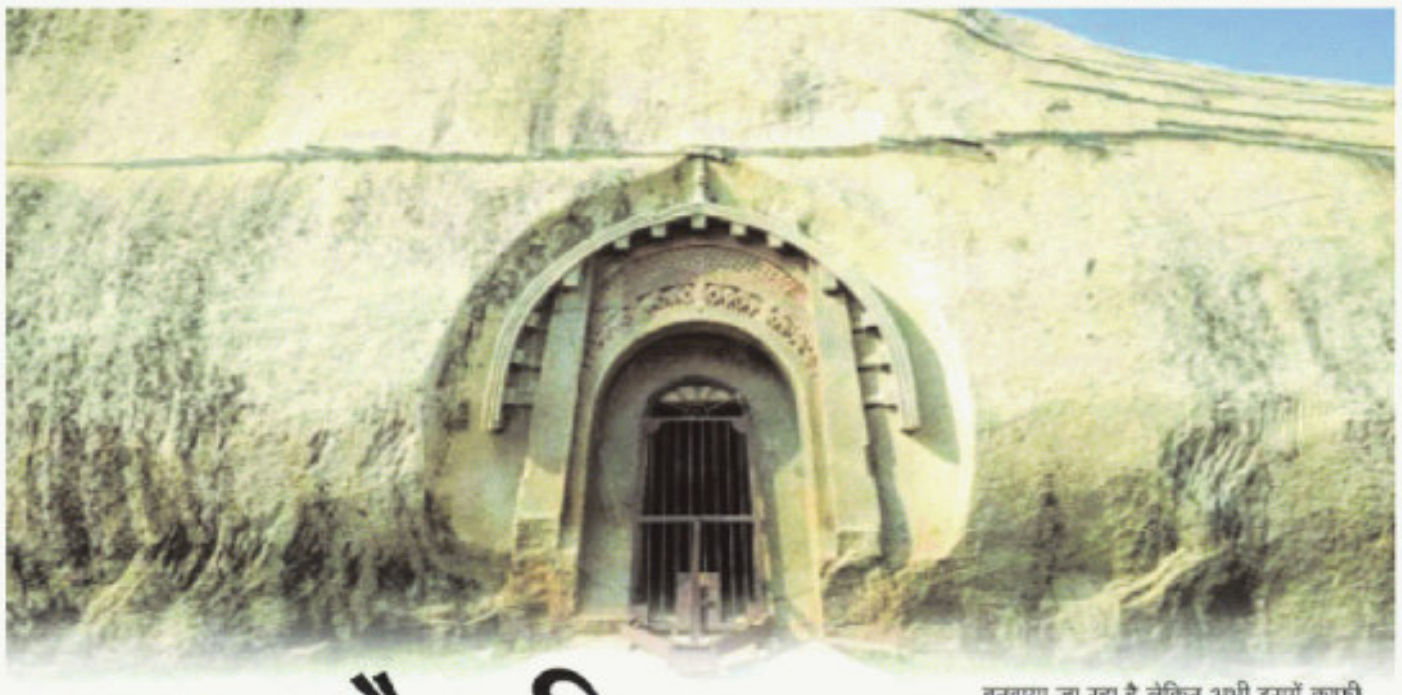

आस्था और इतिहास का खूबसूरत संगम है वाणावर की गुफाएं!

आप सभी जानते होंगे कि पहले आदिमानव के जमाने में गुफाएं उनके रहने का स्थान हुआ करती थी। वह समय ऐसा था जब गुफाएं उन लोगों के लिए एक सुरक्षित घर हुआ करती थी। इतना ही नहीं गुफाएं अलग-अलग मौसम से बचाने का काम करती थी। जंगली जानवर से लोगों की रक्षा किया करती थी। उन गुफाओं के बारे में जानना और वहां जाना अपने आप में बहुत खास है। आज हम एक ऐसी गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत संगम है। वह गुफा है वाणावर की गुफाएं।

वाणावर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। वाणावर की पहाड़ियों पर स्थित यह गुफाएं भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यह गुफाएं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी और अजीव संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल थी।

गुफाओं के पास है सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर

वाणावर की गुफाओं में एक शिव मंदिर भी स्थित है। जिसे सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सातवीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह बिहार के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यह वाणावर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सावन के महीने में इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वैसे तो प्रत्येक दिन लोग यहां जल चढ़ाने आते हैं। लेकिन सावन के महीने में यहां का वातावरण ही कुछ और होता है।

वाणावर गुफाओं की विशेषताएं

- वाणावर की गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है। इन गुफाओं में कुल सात गुफाएं हैं। इनमें से चार गुफाएं वाणावर पहाड़ियों पर और तीन गुफाएं नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित है।
- इन गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण शिल्प और मूर्तिया हैं। इनमें से कुछ शिल्प और मूर्तिया इतनी सुंदर है कि वह आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है।
- इन गुफाओं में बुद्ध, बुद्धिसत्व और अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियां है इनके अलावा इन गुफाओं में कई अन्य शिल्प भी है जिनमें पशुओं, पक्षियों और फूलों की मूर्तियां आदि शामिल है।
- दिन पर दिन इन गुफाओं को और भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी स्तर पर काम चल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है।
- यहां हर साल वाणावर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में लोग बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लेते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने में लोगों को आसानी हो इसके लिए रोपवे भी बनवाया जा रहा है लेकिन अभी इसमें काफी समय लग रहा है।

वाणावर की गुफाओं का महत्व

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। यह गुफाएं प्राचीन इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुफाओं में मौजूद शिल्प और मूर्तियों से हमें बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान होती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहां हर साल हजारों लोग इन गुफाओं को देखने और उनकी प्राचीन संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इन गुफाओं को हजारों साल पहले पहाड़ों को सावधानी से काटकर बनाया गया था। इन गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी है। आपको बता दें, इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख है। यह लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए है, जिसे गाइड पढ़कर विस्तार से बताते और समझाते हैं।

सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई थीं गुफाएं

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। इनमें चार वाणावर पहाड़ियों पर और तीन पास में ही नागार्जुन की पहाड़ियों पर हैं। पहाड़ों को सावधानी से काट कर हजारों साल पहले इंसान इस बेहद सुंदर गुफाओं को बनाया। इनमें से कई गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी चिकनाई आज के समय में लगाई जाने वाली टाइल्स से कम नहीं है। मौर्य काल की यह स्थापत्य कला पर्यटकों को आश्चर्य से भर देती है। इनका निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। इसमें कर्ण चौपर, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा अपनी स्थापत्य कला के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। ब्राह्मी लिपि के जानकार इसे पढ़ और समझ पाते हैं। गाइड इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

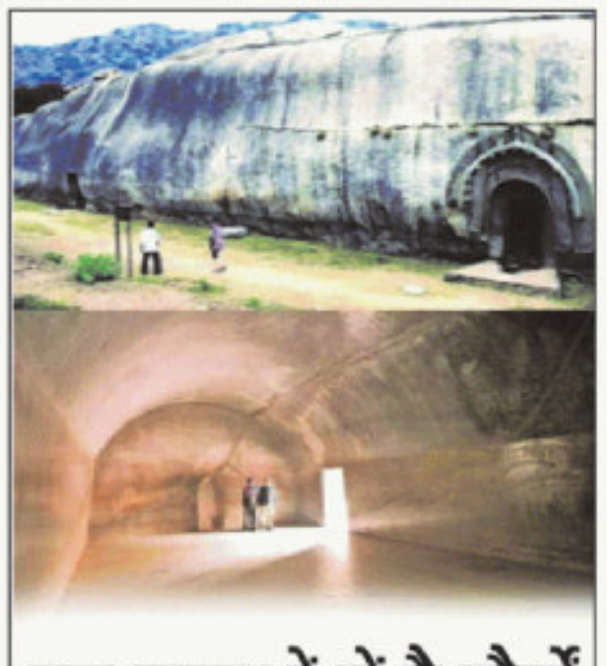

इन गुफाओं में है मौर्यों का खजाना, आज भी दबे हैं यहां कई रहस्य

बिहार की धरती काफी ऐतिहासिक रही है। इस धरती पर जहां कई शूरवीरों ने जन्म लिया और एक नई इबारत लिखी,वहीं प्राचीनता की बात करें तो बिहार में कई ऐसी धरोहर हैं, जो दुनिया भर में लोकप्रिय रही हैं। इन्हीं में से एक धरोहर है बराबर की गुफाएं। ये गुफा भारत की ऐसी सबसे पुरानी गुफा है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यही नहीं, इनमें मौर्य काल की वास्तुकला और शिलालेख आज भी मौजूद हैं।

कहां है ये गुफाएं...

- ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- इन गुफाओं को 'सतघरवा' भी कहते हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल (322–185 ईसा पूर्व) से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है।
- ये गुफाएं बराबर (चार गुफाएं) और नागार्जुनी (तीन गुफाएं) की जुड़वां पहाड़ियों में स्थित हैं।
- अधिकतर गुफाएं दो कक्षों की बनी है जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है।

कौन-कौन सी हैं गुफाएं...

बराबर पहाड़ी में हैं ये चार गुफाएं...
- लोमस ऋषि गुफा
- सुदामा गुफा
- करण चौपर
- विश्व झोपरी

नागार्जुन गुफा
- गोपी गुफा
- भायक गुफा
- वैदतिका गुफा

अन्दर से कैसी हैं बराबर गुफाएं...

गुफाओं की एंट्रेंस वॉल और दरवाजों पर कई शिलालेख हैं, जो बताते हैं कि यहां कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये गुफाएं मगरमच्छ के समान नजर आने वाली चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। गुफाओं में बने कमरे के इंटीरियर में पॉलिश है, जो आज भी सुरक्षित है।

चट्टानों को काटकर बनाए गए कमरे

चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कमरे अशोक (273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व) और उनके पुत्र दशरथ के मौर्य काल, तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को पनपने का अवसर दिया।

इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के संन्यासियों द्वारा किया गया था जिनकी स्थापना मक्खाली गोसाला द्वारा की गयी थी, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शुक्रवार 13 मार्च 2026

ट्रंप का असली चेहरा सामने आया

शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने की तमन्ना लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने %ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व% चलाकर वेनेजुएला पर शनिवार स्थानीय समय के अनुसार 02ः01 बजे हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया लोरेस समेत गिर तार कर लिया और उन्हें हवाई मार्ग से अमेरिका ले आया गया। अमेरिकी विमान से मादुरो को जब उतारा जा रहा था तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हथकड़ियां भी लगी थीं। यह दृश्य देखकर इतिहास खुद को दोहराता है, वाली मिसाल याद आ गई। लेकिन यह नहीं पता था कि इतिहास इतनी जल्दी दोहराया जाएगा। अभी 21वीं सदी शुरु ही हुई थी कि इराक पर अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों की तलाश के नाम पर आक्रमण किया और तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन को गिर तार कर फांसी पर भी चढ़ा दिया। फिर पता चला कि ऐसे कोई हथियार इराक में थे ही नहीं। शायद अमेरिका को हथियारों की तलाश थी भी नहीं, उसे इराक के प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा चाहिए था, जो उसे मिल गया। यही खेल अब वेनेजुएला में खेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर गलत तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाने के साथ ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उनका कहना है कि अब मादुरो को पत्नी समेत अमेरिका की कड़ी न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। मानो सारी दुनिया का ठेका अमेरिका को मिल चुका है कि उसका राष्ट्रपति जब चाहे किसी संप्रभु देश पर आक्रमण कर दे और वहां के नेता को अमेरिकी कटघरे में खड़ा कर दे। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों, स्त्री अधिकार को ठेंगा दिखाते हुए राष्ट्र प्रमुख के साथ उनकी पत्नी को भी गिर तार कर ले। चिंता की बात यह है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जिन उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को बनाया गया था, वह पूरी तरह नख–दंत विहीन और लाचार बन चुकी है। घर के अशक्त बूढ़े बुर्जुग उपद्रवी बच्चों को मत लड़ो–मत लड़ो जैसी लाचारगी भरी नसीहत देते हैं, वैसा ही हाल संरा का हो चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका समर्थित हमले हो रहे हैं और संरा बयान जारी करने से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इससे बेहतर है कि संरा को मिटा कर नए सिरे से कोई ऐसी वैश्विक संस्था बनाई जाए, जो वाकई दुनिया में शांति स्थापना का काम कर सके। लेकिन इसकी पहल कौन करेगा ये भी विचारणीय है। जब भारत में प.जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया तो तीसरी दुनिया के देशों को अपने अस्तित्व और स मान को बचाए रखने के लिए नया मंच मिला। आज के भारत का हाल तो ऐसा है कि ट्रंप पचासों बार पाकिस्तान के समकक्ष हमें रखते हुए युद्धविराम के दावे कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी माई डियर फ्रेंड ट्रंप का नाम ही जपते रहे। अब भी वेनेजुएला के घटनाक्रम पर नरेन्द्र मोदी की कोई सीधी टिप्पणी देखने नहीं मिली है, बल्कि एस जयशंकर का बयान आया है कि हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के ज़रिए और शांतिपूर्ण तरीक़े से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत को बताना चाहिए कि सभी संबंधित पक्षों से उसका तात्पर्य क्या है। क्यों मोदी पहले चीन का नाम लेने से कतरा रहे थे और अब अमेरिका को सीधे नहीं कह रहे कि उसका इस तरह आक्रमण करना गलत है। मान लें कि निकोलस मादुरो ने अपने देश में कुछ गलत किया है या वैश्विक स्तर पर किसी अपराध में संलग्न हैं, तो उन पर कार्रवाई के लिए उनके अपने देश की न्याय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय अदालत है। ट्रंप यहां किस हैसियत से घुसे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने बिल्कु ल ठीक कहा है कि वेनेजुएला के नेता को हिंसक तरीक़े से पकड़ना पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक और बेहद ख़तरनाक मिसाल है। क्यूबा ने कहा कि वेनेजुएला पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करता है। रूस ने भी इस हमले को गलत बताया है वहीं चीन ने कहा है कि एक संप्रभु देश के ख़िलाफ़ अमेरिका के खुलेआम बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ कार्रवाई से वह बहुत हैरान है और इसकी कड़ी निंदा करता है।

स्त्रियों के प्रति कुंद होतीं जन संवेदनाएं

कनुप्रिया

एक समय था जब निर्भया के लिये पूरा देश हिल उठा था, उसके प्रति इंसाफ़ के लिये सड़कों पर आ गया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सत्ताच्युत होने में निर्भयाकांड एक बड़ा कारण बन गया था, जबकि सरकार ने तुरंत उसका अपने ख़र्च पर इलाज कराया, आरोपियों को गिर तार किया, फांसी हुई। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिये न्याय की लड़ाई लड़ी ही जा रही है, उन्नाव की पीड़िता के घाव सूखे नही हैं, हाथरस की पीड़िता के साथ हुआ अन्याय आवाज़ की तलाश में ही है कि कानपुर से 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की ख़बर आ गई, इस बार बलात्कारी एक यू ट्यूबर और सब इंस्पेक्टर है। सड़क से बच्ची का अपहरण करके, 2 घण्टे उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे बुरी हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस ने पहले तो प्राथमिकी दज़ ही नहीं की, बाद में सीनियर पुलिस अफसर तक पीड़िता के परिजन पहुंचे तो रिपोर्ट दज़ हुई तब तक बलात्कारी पुलिस वाला फ़रार हो गया।

दुखद ये भी है कि अब ऐसी ख़बरें आती हैं तो हम चौंकते भी नहीं, ये हमारी चेतना को झिंझोड़ता ही नहीं। ऐसी घटनाओं का होना मानो हमारे सामाजिक दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया है। आप गूगल करेंगे तो हर दिन स्त्रियों, बच्चियों के प्रति जघन्य अपराध की कोई न कोई ख़बर मिल ही जायेगी और सबसे ऊपर जिस प्रदेश का नाम मिलेगा वो अपने आप में एक मिनी हिन्दू राष्ट्र है। वहां धर्म के सबसे बड़े ठेकेदारों की डबल इंजन सरकार है।

दरअसल पिछले 11 सालों में जिस योजना पर सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है बलात्कारी बचाओ योजना। बल्कि जिस शिद्दत से बलात्कारियों को प्रोत्साहन दिया गया है, इसे बलात्कारी बनाओ योजना भी कहें तो अतिशयोक्ति नही होगी, दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। बलात्कारियों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें लगातार ज़मानत दी जाती है (हाल ही में बलात्कारी बाबा आसाराम को 10 महीने में चौथी बार ज़मानत मिली और राम रहीम को 15 वीं बार पैरोल)। जेल से बाहर आने पर बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, कभी उनके पक्ष में भगवा झंडों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। कभी उन पर क़ानून की धार पूरी तरह कुंद हो जाती है, वो ऐसी मार करता है कि अपराधी को चोट ही नहीं लगती। मसलन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) और 354ए (लैंगिक उत्पीड़न) के तहत %चार्ज फ्रेम' हुए, मगर जांच एजेंसियों ने उन्हें कभी गिर तार ही नहीं किया, 2023 से वो ज़मानत पर हैं, उनकी जमानत का कभी विरोध भी नहीं हुआ। मीडिया ज़्यादातर बलात्कार की घटनाओं पर चुप रहता है, चर्चा नहीं करता, मानो यह सामाजिक चिंता का विषय ही नहीं।

उधर यौन शोषण के प्रति न्यायालयों का रवैया ये है कि न्याय के लिये पीड़िताओं को न्यायालयों के ख़िलाफ़ धरना देने की नौबत आ जाती है। पिछले ही साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और कपड़े उतारने का प्रयास करना, बलात्कार की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी कई शर्मनाक और महिलाओं को न्याय के लिये हतोत्साहित करती हुई टिप्पणियां पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रदेशों के न्यायालयों ने की हैं, जो समाज में बलात्कारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देती हैं।इस सबके बाद त्रासदी ये है कि पीड़िताओं के ख़िलाफ़ ही सोशल मीडिया पर उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तोड़ने और उनके संघर्ष के प्रति समाज के भीतर नकारात्मक नज़रिया बनाने के लिए अभियान चलाये जाते हैं। मसलन महिला पहलवानों के ख़िलाफ़ ऐसा ही अभियान चलाया गया था कि उनका आंदोलन राजनीतिक है, उनके यौन शोषण की बात झूठ है और आरोपी बिल्कुल निर्दोष है इत्यादि इत्यादि। अब एक अभियान उन्नाव की पीड़िता के विरुद्ध चलाया जा रहा है, एआई के ज़रिए उनके झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि वह स्वयं एक बेशरम महिला है और उसने जानबूझ कर आरोपी कुलदीप सेंगर को फंसाया है। तिस पर करेले पर नीम चढ़ा यह कि खुद सरकार बहादुर यौन शोषकों और बलात्कारियों के लिये वोट मांगते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उनके ख़िलाफ़ मामलों पर पूरी तरह चुप्पी मार जाते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य यौन अपराधों पर सरकार ने जिस तरह ख़ामोशी इ तियार की उससे साबित हुआ कि सरकार किस क़दर महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। ज़्यादा जानें सोशल मीडिया परामर्श युवा मनोरंजन खेल उपकरण मु य शीर्षक विशेष रिपोर्ट सदस्यता बॉलीवुड समाचार कविता संग्रह ताज़ा खबरें अपडेट राजनीतिक विश्लेषण पुस्तक साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण आख़िर इससे अधिक प्रोत्साहन बलात्कार को और कैसे दिया जा सकता है? एक बलात्कारी समाज बनाने में सरकार की तरफ़ से कोई कमी रही हो तो बताइए। अब इतना ही बचता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक मंचों पर यौन शोषकों को समाज के मॉडल की तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। उनके नाम पर पुरस्कार बांटे जायें, उनकी प्रशंसा में पुस्तकें लिखी जायें, सड़कों और स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखे जायें, उन्हें पद्म स मान से स मानित किया जाये, ताकि एक स पूर्ण बलात्कारी समाज का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके, उसे उपलब्धि की तरह दिखाया जा सके। और ये सब हो रहा है घोर सनातनी, धार्मिक सरकारों के राज में, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दंभ भरती हैं और मंदिरों की प्रतिष्ठा पर्व मना–मना कर ही गर्वित हुए जा रही है। धार्मिकता का आलम ये है कि धर्म के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे संत और बाबा लोग स्त्रियों के ख़िलाफ़ अनर्गल बयान देते हैं, जिससे उनकी गरिमा को कड़ी चोट पहुंचती है। मसलन धीरेन्द्र शास्त्री का एक शर्मनाक बयान जिसमें उसने बिना सिंदूर की मांग वाली महिलाओं को ख़ाली प्लॉट की संज्ञा दी गई, जिस पर कोई भी क़ब्ज़ा कर सकता है। बागेश्वर धाम में लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे तो बिना जांच किये आरोप लगाने वाले प्रोफेसर के ख़िलाफ़ ही रिपोर्ट दज़ कर ली गई। बाबा अनिरुद्ध आचार्य ने अपने सत्संग में कहा कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, बाबा प्रेमानंद का कहना है कि सौ में से अब 2–4 लड़कियों ही पवित्र होती होंगी। ज़्यादा जानें साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण प्रादेशिक समाचार विविध समाचार युवा मनोरंजन ई–पेपर सदस्यता सोशल मीडिया परामर्श राजनीति समाचार डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ साक्षात्कार संग्रह बजट संबंधित वित्तीय सेवाएँ ये बोल–वचन तब हैं जब देश के अधिकतर बाबाओं पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। यहां तक कि सेलिब्रिटी बाबा सदुरु के आश्रम में भी बच्चों के यौन शोषण के आरोप कई अभिभावकों ने लगाए हैं। मगर धर्मान्ध लोगों की सोचने–समझने की शक्ति इस क़दर छीन लेता है कि फिर भी ये तथाकथित धार्मिक गुरु पूज्य बने रहते हैं। भक्तों में उनकी पद धूलि लेने के लिये ऐसी भगदड़ मचती है कि लोग दब–कुचल कर जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसा कि हाथरस के एक गांव में सूरजपाल उफ़ 'भोले बाबा के मामले में हुआ। सच तो ये है कि धर्म एक ऐसा गटर हो चुका है जिसमें समाज के सबसे सड़े हुए, गंदे तबके को प्राणवायु मिलती है, उसके गुनाहों को संरक्षण मिलता है। धर्म, अपराधियों और यौन शोषकों की अंतिम शरणस्थली बन चुका है, तभी तो धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में अश्लील कंटेंट और घोटालों की आरोपी शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर शामिल होकर स्याह से सफ़ेद हो जाती हैं। एक समय था जब निर्भया के लिये पूरा देश हिल उठा था, उसके प्रति इंसाफ़ के लिये सड़कों पर आ गया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सत्ताच्युत होने में निर्भयाकांड एक बड़ा कारण बन गया था, जबकि सरकार ने तुरंत उसका अपने ख़र्च पर इलाज कराया, आरोपियों को गिर तार किया, फांसी हुई और राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को पढ़ाने लिखाने और पायलट बनाने में निजी तौर पर मदद की। मगर इन सबसे भी जनता के भीतर आक्रोश कम नहीं हुआ था। आज उसी देश की जनता की स वेदनाएं स्त्रियों के प्रति मानो कुंद हो गईं, जबकि देश की जनता पहले से ज़्यादा धार्मिक हैं, देश में पहले से कहीं ज़्यादा मंदिर बन रहे हैं और धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं। मगर स्त्रियों पर, मासूम बच्चियों पर यौन शोषण, बलात्कार और हत्या की ख़बरें आती हैं और चली जाती हैं। जनता आक्रोशित नहीं होती, मानो हिन्दू राष्ट्र के लिये स्त्रियों की अस्मिता और गरिमा की बलि स्वीकार्य है, बल्कि ऐसा होना उसने सामान्य मान लिया है।

धार्मिक जलसों का शोर और सर्दी के सितम से मरते लोग

अनिल जैन

शीतलहर, बाढ़ और भीषण गरमी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं है। यह तो पहले से आती रही है और आती रहेंगी। इन्हें रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है तो इनसे होने वाली जान–माल की तबाही को, जो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की ईमानदार इच्छाशक्ति से ही संभव है। ताजा शीतलहर और उससे होने वाली मौतें हमें बता रही हैं कि जब मौसम के हल्के से विचलन का सामना करने की हमारी तैयारी नहीं है। सरकारी स्तर पर धार्मिक जलसों और विभाजनकारी भाषणों के बीच इस समय देश के विभिन्न इलाकों में शीतलहर कहर बरपा रही है, जिससे हर साल की तरह देश के विभिन्न इलाकों से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोग सर्दी की ठिठुरन से मौत की नींद सो चुके हैं। वैसे इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। कहीं भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें तो कहीं गरीबी और कर्ज के बोझ से त्रस्त किसानों और छोटे कारोबारियों की खुदकुशी और कहीं जातीय व सांप्रदायिक हिंसा में होने वाली मौतों के जारी सिलसिले के बीच हर साल ही सर्दी की ठिठुरन, लू के थपेड़ों और बारिश–बाढ़ से भी लोग मरते ही रहते हैं।

मौसम की अति के चलते असमय होने वाली ये मौतें हमारे उस भारत की नग्न सच्चाइयां हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ये सच्चाइयां सिर्फ हमारी सरकारों के शाइनिंग इंडिया, भारत निर्माण न्यू इंडिया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया% %मैक इन इंडिया% जैसे हवा–हवाई कार्यक्रमों और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने जैसे गुलाबी दावों की ही खिल्ली नहीं उड़ाती हैं, बल्कि व्यवस्था पर काबिज लोगों की नालायकी और संवेदनहीनता को भी उजागर करती हैं।

वैसे सर्दी हमारे नियमित मौसम चक्र का ही हिस्सा है। कड़ाके की सर्दी इसका हल्का सा विचलन भर है। सर्दी और भीषण सर्दी अंत में हमें कई तरह से फायदा ही पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की सर्दी हमें आश्वस्त करती है कि ग्लोबल वार्मिंग उतनी सन्निकट नहीं है, जितना कि अक्सर हम मान बैठते हैं। मौसम की मौजूदा अति भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर कुछ साल के बाद हमारा इससे सामना होता रहता है– कभी सर्दी में, कभी गरमी में तो कभी बारिश में।

ज्यादातर भारतीय इस मायने में खुशनसीब हैं कि उन्हें मौसम की विविधताएं देखने को मिलती हैं। अन्यथा दुनिया में ऐसे कम ही इलाके हैं जहां हर मौसम का मज़ा लिया जा सके। प्रत्येक मौसम अपने रौद्र रूप में भी सुंदर होता है, बशर्ते कि उसकी मार से लोगों को बचाने के इंतज़ामात हों। दुनिया में संभवत भारत ही ऐसा देश है, जहां हर मौसम की अति होने पर लोगों के मरने की खबरें आने लगती है। हकीकत यह है कि लोग मौसम की अति से नहीं मरते, वे मरते हैं अपनी गरीबी से, अपनी साधनहीनता से और व्यवस्था तंत्र की नाकामी या लापरवाही की वज़ह से। यूरोप के देशों में सरकारें मौसम की अति का मुकाबला करने के चाक–चौबंद इंतजाम करती हैं, इसलिए वहां लोग हर मौसम का तरह–तरह से लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे देश में भी खाया–अघाया तबका ऐसा ही करता है, जिसके पास हर मौसम की अति का सामना करने और उसका लुत्फ उठाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

भारत के ज्यादातर हिस्सों में यूरोप जैसी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हमारे यहां जब हिमालय परिवार की पहाड़ियों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलती है तो देश के विभिन्न इलाकों में सर्दी की ठिठुरन से होने वाली मौतों के आंकड़े आने लगते हैं। अभी जो शीतलहर जारी है, वह सिर्फ हिमालयी प्रदेशों और गंगा–यमुना के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और रेगिस्तानी राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और सुदूर छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा तक ठंड से ठिठुर रहे हैं। सर्दी के इस सितम से सामान्य जनजीवन बुरी तरह गड़बड़ा गया है। देश के विभिन्न इलाकों से बेघर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि बड़े शहरों से निकलने वाले समाचारपत्रों में अब सर्दी से होने वाली मौतों की खबरों को जगह मिलनी लगभग बंद हो गई है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। तब अखबारों में नियमित खबरें छपती थी और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट उन खबरों का संज्ञान लेकर संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से जवाबतलब करते थे। उन्हें साधनहीन लोगों के उचित इंतज़ाम करने के निर्देश देते थे। अब सरकारों का मीडिया प्रबंधन तंत्र ऐसी खबरों को छपने से रोकने मे सफल होने लगा है। यही वजह है कि अब कुछ गिने–चुने अखबारों में ही सर्दी से लोगों के मरने की खबरें छपती हैं। टेलीविजन चैनल तो सुबह से रात तक हिंदू–मुसलमान करने में ही व्यस्त रहते हैं। अगर थोड़ी फुरसत मिलती भी है तो उनके लिए अपने दर्शकों को यह बताना ज्यादा जरूरी होता है कि फलां अभिनेत्री कब शादी करने वाली है, फलां अभिनेत्री कब मां बनने वाली है और किस अभिनेत्री का किस अभिनेता से तलाक होने वाला है या फिर वे यह बताते हैं कि लोग सर्दी का लुत्फ़ लेने के लिए क्या–क्या कर रहे हैं और कहां–कहां जा रहे हैं।

सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 800 से ज्यादा लोग सर्दी के सितम से मरते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2015 में 1149 लोगों की मौत हुई थी। हकीकत यह है कि अगर समूचे भारत के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो हर साल सर्दी से मरने वालों की सं या हजारों में पहुंचती है। ज्यादातर मौतें बड़े शहरों और महानगरों में होती हैं। जो मरते हैं, उनमें से ज्यादातर बेघर होते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में दूरदराज़ के इलाकों से अपने ही राज्य में या दूसरे राज्यों के बड़े शहरों या महानगरों में जाते हैं, ताकि मेहनत–मजदूरी कर अपने परिवार के जिंदा रह सकने लायक कुछ कमा सकें। मौसम कोई भी हो, जब भी उसकी अति दरवाजे पर दस्तक देती है तो हमारी सारी व्यवस्थाओं की पोल का पिटारा खुलने लगता है। फिलहाल सर्दी की बात की जाए तो हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा पोल खुली है पूर्वानुमान लगाने वाले मौसम विभाग की। बारिश का मौसम खत्म होते ही हमें बताया गया था कि इस बार सर्दी कम पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाओं के बीच इस भविष्यवाणी पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई थी, परन्तु जैसे ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो फिर मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि यह कड़ाके की ठंड चंद दिनों की ही मेहमान है। जल्द ही मौजूदा उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा जानें युवा मनोरंजन समाचार पत्र वितरण सेवा विदेश यात्रा योजनाएँ प्रादेशिक समाचार हिंदी भाषा शिक्षण मनोरंजन पत्रिका खेल उपकरण संपादकीय लेख सोशल मीडिया परामर्श कविता संग्रह सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं, बाकी सरकारी महकमों का भी यही हाल है। फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और भूमिगत पारपथों पर रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था अभी भी कई जगह अधूरी है या बिल्कुल ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कई बार इस मामले में राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पु ता बंदोबस्त करने के निर्देश दे चुका है। जहां रैन बसेरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है, वहां अलाव जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाती है, लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में मौसम की मार से लोगों के मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह है शहरी नियोजन में सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता। जब से आवासीय कॉलोनियों की बसाहट के मामले में विकास प्राधिकरणों और गृह निर्माण मंडलों के बजाय निजी भवन निर्माताओं और कॉलोनाइज़रों का दखल बढ़ा है, तब से रोज कमाकर रोज खाने वालों और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजनाएं हाशिए पर खिसकती गई हैं। करोड़ों लोग आज भी फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर और टाट या प्लास्टिक आदि से बनी झोपड़ियों में रात बिताते हैं। बहुत से लोगों के पास तो पहनने को गरम कपड़े या ओढ़ने को रजाई–कंबल तो दूर तापने को सूखी लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को मौसम की मार से बचाने के लिए अदालतें हर साल सरकारों और स्थानीय निकायों को लताड़ती रहती हैं, लेकिन सरकारीतंत्र की मोटी चमड़ी पर ऐसी लताड़ों का कोई असर नहीं होता है। शीतलहर, बाढ़ और भीषण गरमी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं है।

विविध समाचार

पर्यटन के मानचित्र पर कांगड़ा जिले को मिलेगी नई पहचान : मुकेश अग्निहोत्री

धर्मशाला १२/०३ (संवाददाता): उप– मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित जिला स्तरीय 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सेना, पुलिस, होम गार्ड्स, एनएसएस और स्काउट एवं गाइड्स की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत शानदार परेड की सलामी ली। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया गया है जिसके कारण पिछले तीन वर्षों में 26 हजार 683 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में ही पर्यटन निगम का राज्य मुख्यालय स्थान्तिरत किया गया है। देहरा के बनखंडी में 619 करोड़ की लागत से अरण्य वन्यप्राणी उद्यान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले के नड्डी में एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन स्थापित की जाएगी जिसकी कुल लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी और इसे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके रनवे की लंबाई को 1376 मीटर से बढ़ाकर इसे 3010 मीटर किया जाएगा यहां एयरबस एवं रात्रि लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और 1332 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पालमपुर में हेलिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। पौंग क्षेत्र में पर्यटन, वॉटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार एनआईटी हमीरपुर विशेषज्ञों के सहयोग से ज्वालामुखी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर कार्य कर रही है जिस के लिए 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है जबकि शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 150 करोड़ रूपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि देहरा उप–मंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ई–टैक्सी खरीदने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में बेहतर पेयजल और सिंचाई के लिए सरकार ने 354 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें से 192 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के लिए 3360 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए 213.40 करोड़ रुपये की सुकाहार मध्यम सिंचाई परियोजना तथा ज्वालामुखी क्षेत्र की पंचायतों के लिए 333.49 करोड़ रुपये की पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में 9 सीवरेज योजनाओं के लिए 433.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और 93.52 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना के लिए कुल स्वीकृत 643.68 करोड़ रुपये में से 301.48 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुरानी डीजल बसों के स्थान पर 297 नई विद्युत बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जा रही हैं जिस पर 424 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राज्य के विश्राम गृहों तथा सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 310 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार 41 अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) भी विकसित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के कंदरोडी में 268 करोड़ रूपये की लागत से नया पेप्सी प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसमें 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पशु पालकों की आय में बढ़ोतरी के लिए कांगड़ा में ढगवार में 201 रुपये करोड़ रूपये की लागत से विश्वस्तरीय दूध प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उप–मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन के खिलाफ समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए ताकि युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो। सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियायन चलाया है और नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रत्न, आशीष बुटेल और विधायक मलेंद्र राजन, प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, एपीएमसी के चेयरमैन नीशू मोंगरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा, नगर निगम महापौर नीनू शर्मा, पूर्व महापौर देवेन्द्र जग्गी, पार्षद अनुराग, ओंकार नेहरिया, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित थे।

श्री गुरु रविदास जी के समानता के संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए पंजाब सरकार की अनूठी पहल

चंडीगढ १२/०३ (संवाददाता): छह सदियों पहले श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके तहत जालंधर जिले में डेरा बल्लां के निकट श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 10 करोड़ रुपये की लागत से कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री चीमा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए आज कुल तीन रजिस्ट्रियां क्रमशः गाँव नौगजा (64 कनाल 5 मरलेकृलागत 5,40,98,500 रुपये), गाँव फरीदपुर की पहली रजिस्ट्री (2 कनालकृलागत 16,74,000 रुपये) तथा गाँव फरीदपुर में दूसरी रजिस्ट्री (10 कनाल 14 मरलेकृलागत 1,44,62,150 रुपये) की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुल तीनों रजिस्ट्रियों का क्षेत्रफल 76 कनाल 19 मरले है और कुल लागत 7,02,54,659 रुपये है। स चीमा ने कहा, "हमें इस नेक कार्य में योगदान देने पर गर्व है। हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रचारित समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए समर्पित है।" उन्होंने आगे कहा, "यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ सिद्ध होगा।" इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना और सामाजिक–आर्थिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य सेमिनारों, प्रकाशनों और समुदाय–आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का शोध, संरक्षण और प्रचार करना है।

विधायक परगट सिंह ने सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच संगतों को दी गुरुपर्व की शुभकामनाएं, लिया संतों का आशीर्वाद

जालंधर १२/०३ (संवाददाता): पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह वीरवार को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें गुरुपर्व के मौके पर बनारस (वाराणसी) के लिए रवाना हुई ट्रेन को लेकर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने डेरा सचखंड बल्लां के गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और बनारस जाने वाली संगतों को गुरुपर्व की शुभकामनाएं दीं।उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का रास्ता दिखाया है। उनके दिए गुरु रविदास जी का जीवन उपदेश समाज को एकता और सेवा के लिए प्रेरित करता हैं। उन्होंने कहा कि गुरुपर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालु हर साल गुरु महाराज की जन्मस्थली बनारस (वाराणसी) में मत्था टेकने जाते हैं। यह परंपरा वर्षों से श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। उनके साथ कांग्रेसी नेता सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जिला प्रधान शहरी रजिंदर बेरी, विधायक सुखविंदर कोटली और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर भी अन्य नेता भी शामिल रहे।

भक्ति आंदोलन के सूर्य संत शिरोणि रविदास

भारतीय इतिहास का मध्यकाल (15वीं–16वीं शताब्दी) न केवल राजनीतिक उथल–पुथल का दौर था, बल्कि तत्कालीन भारत एक गहरे वैचारिक संक्रमण काल से भी गुजर रहा था। एक ओर विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से भारतीय समाज अपनी रक्षात्मक मुद्रा में था, वहीं दूसरी ओर आंतरिक रूप से जातिवाद, छुआछूत और विद्वता नहीं बल्कि जन्मना ब्राह्मणवाद की कट्टरता ने समाज को खोखला कर दिया था। ऐसे अंधकारमय समय में काशी की धरती पर विक्रम संवत 1433 में माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास का प्रकटीकरण केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक मानवीय क्रांति का सूत्रपात था।इस आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के कालखंड में संत रविदास (जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है) एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बनकर उभरे, जिन्होंने धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं को चुनौती दी और भक्ति को कर्मकांडों के चंगुल से मुक्त कर सीधे मानवतासे जोड़ दिया। उनका जीवन और दर्शन आज भी सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला माना जाता है। उन्होंने धर्म को मंदिर–मस्जिद की दीवारों से निकालकर इंसानियतकी चौखट पर ला खड़ा किया।

संत रविदास का जन्म वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर ग्राम में विक्रम संवत 1433 में माघ पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता संतोख दास और माता कलसां देवी थे। वे एक चर्मकार परिवार से संबंधित थे। तत्कालीन समाज में इस कार्य को करने वाली जातियों को अछूत और हेय दृष्टि से देखा जाता था।लेकिन संत रविदास ने अपने पैतृक व्यवसाय (जूते बनाना) को कभी नहीं त्यागा। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने वाली नियत महत्वपूर्ण होती है। वे जूते गांठते हुए भी ईश्वर का सिमरन करते थे। यही उनके जीवन का पहला बड़ा सुधार था–श्रम की गरिमाकी स्थापना।उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। रामानंद के सान्निध्य व प्रभाव से रविदास कीआध्यात्मिक दृष्टि व्यापक हुई, जहां उन्होंने सीखा कि जाति–पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।रविदास का स्वामी रामानंद का शिष्य बनना मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रामानंद ने जाति–पाति पूछे नहीं कोई का जो नारा दिया था, रविदास उसके जीवंत उदाहरण बने।कहा जाता है कि जब रविदास ने रामानंद से दीक्षा मांगी, तो काशी के पंडितों ने इसका विरोध किया। तब रामानंद ने उनके अंतर्मन की शुद्धि को देखकर उन्हें अपनाया। रविदास ने गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपनी कर्मस्थली जूते बनाने की दुकानपर ही चरितार्थ किया। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर को पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपना कर्म करना ही तपस्याहै।उन्होंनेसामाजिक सुधार के लिए जातिवाद पर प्रहार और समानता का शंखनाद किया।रविदास का सबसे बड़ा योगदान जातिआधारित ऊँच–नीच के विरुद्ध उनका साहसी संघर्ष था। उन्होंने शास्त्रों की उन दकियानूसी व्याख्याओं को नकारा जो मनुष्य को जन्म के आधार पर विभाजित करती थीं।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की–

रैदास जन्म के कारनै, होत न कोई नीच।
नर को नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच।।

अर्थात– मनुष्य जन्म से नीच नहीं होता, बल्कि उसके बुरे कर्म ही उसे नीच बनाते हैं।

उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान और पंच तत्वों से निर्मित हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि सबका सृजनहार (ईश्वर) एक है, तो इंसानों में भेद कैसा? उनके इस दर्शन ने समाज के वंचित वर्गों में आत्म–सम्मान का संचार किया। रविदास ने अपनी वाणी में एक ऐसे आदर्श शहर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। यह केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक घोषणापत्र था।उनके अनुसार बेगमपुरा अर्थात बिना–गम का शहर एक ऐसा स्थान है, जहां दुःख व चिंता (तसवीस) का नामोनिशान नहीं है।कोई कर (खिराज) या संपत्ति का भय नहीं है।कोई सामाजिक भेदभाव या ऊँच–नीच नहीं है।सभी नागरिक समान हैं और कहीं भी आने–जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि थॉमस मोर की यूटोपियासे सदियों पहले, रविदास ने एक ऐसे संप्रभु और समतावादी समाज का खाका खींचा था, जो आज के आधुनिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्यके सिद्धांतों से मेल खाता है। रविदास की भक्ति निर्गुणथी, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम अत्यंत सगुण और गहरा था।उनका प्रसिद्ध सूत्र– मन चंगा तो कठौती में गंगा– बाहरी दिखावों, तीर्थ यात्राओं और कर्मकांडों पर सबसे बड़ी चोट थी। उन्होंने सिखाया कि यदि आपका मन पवित्र है और कर्म ईमानदारी भरा है, तो आप जिस बर्तन (कठौती) में काम कर रहे हैं, उसी में गंगा का पुण्य प्राप्त हो सकता है।उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर मेवाड़ की रानी मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु बनाया था। एक चर्मकार संत को एक क्षत्रिय रानी द्वारा गुरु स्वीकार किया जाना मध्यकाल की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। यह इस बात का प्रमाण था कि ज्ञान और भक्ति किसी जाति की बपौती नहीं हैं।

संत रविदास की वाणी सरल, सहज और हृदय को छूने वाली थी। उनकी रचनाओं ने धर्म और भाषा की सीमाओं को तोड़ दिया।उनकी भाषा सरल ब्रज, अवधी और राजस्थानी का मिश्रण है, जिससे वे आम जनता से सीधे जुड़ सके। उनकी वाणी में करुणाऔर विद्रोहका अद्भुत संतुलन है। उनकी आध्यात्मिक महानता, उनके साहित्यिक विरासत की व्यापक स्वीकार्यताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 40 पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिखों के पंचम गुरु, गुरु अर्जुन देव सिंह ने उनकी वाणी को गुरुओं के बराबर सम्मान दिया।उनके पदों में ईश्वर के प्रति समर्पण, विरह और सामाजिक चेतना का अद्भुत मिश्रण है। वे स्वयं को खलास चमारा अर्थात मुक्त चमार कहते थे, जो जाति के बंधनों से ऊपर उठ चुका था।वर्तमान में भी संत रविदास केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं।पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया है, जिसे रविदासिया धर्मके रूप में जाना जाता है।भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. बी.आर. अंबेडकर रविदास के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। संविधान में वर्णित समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य कहीं न कहीं रविदास के बेगमपुराके सपने का ही विस्तार हैं।

संत रविदास का जीवन इस बात का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों और सामाजिक भेदभाव के बावजूद, मनुष्य अपने चरित्र और कर्म से सर्वोच्चता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भक्ति को परलोकसे हटाकर इहलोक(इस संसार) के सुधार से जोड़ा। उनका नारा– रैदास मनुष ना जुड़ सके, जब लौ जाति न जात– आज के खंडित समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी और समाधान है।जब तक संसार में गरीबी, भेदभाव और अन्याय रहेगा, संत रविदास का बेगमपुरामानवता का अंतिम लक्ष्य बना रहेगा। वे केवल एक समुदाय के संत नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मानवतावादी पथप्रदर्शकहैं।मध्यकालीन भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि में बेगमपुरा को मानवीय चेतना का वैश्विक घोषणापत्र और सामाजिक क्रांति का महाकाव्य कहा जा सकता है।संत रविदास का जीवन जहां चर्मकार कुल का संघर्ष का प्रतीक हैं, वहीं प्रतिकूलताओं के बीच प्रज्ञा का उदय का भी द्योतक है।जिस काल में शूद्रों के लिए वेद सुनना भी अपराध माना जाता था, उस काल में एक चर्मकार परिवार में जन्म लेकर ब्रह्म–ज्ञानप्राप्त करना अपने आप में एक विद्रोह था। रविदास ने बचपन से ही सामाजिक अपमान को देखा, लेकिन उनके भीतर घृणा के बजाय करुणाका संचार हुआ।वे बचपन से ही साधु–संतों की सेवा में लगे रहते थे। कथाओं के अनुसारवे अक्सर अपने पिता द्वारा दिए गए धन से भूखे साधुओं को भोजन करा देते थे। उनकी यह परोपकारी प्रवृत्ति आगे चलकर उनके व्यापक मानवतावाद का आधार बनी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कांग्रेस ने भुवनेश्वर में विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

भुवनेश्वर १२/०३ (संवाददाता): कांग्रेस ने सोमवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले भुवनेश्वर के लोअर क्क्ल्न स्क्वायर पर सत्याग्रह (विरोध मार्च) किया। यह विरोध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (विकसित भारत-जी राम जी को नई शुरू की गई विकसित भारत-जी राम जी योजना से बदलने के खिलाफ था। बाद में प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को एक ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ऋत्नक्क्रस् के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार, RGPRS के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन दास और कई वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और समर्थकों ने किया, जो स्त्नहक्रश्वतस् को तुरंत बहाल करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में बैठे।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पंवार ने कहा कि देश के करोड़ों गरीब लोग, जिन्हें उन्होंने देश का असली मालिक बताया, लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने उन्हें स्त्नहक्रश्वतस् के रूप में काम का अधिकार दिया था, जो एक अधिकार-आधारित कानून था। हालांकि, पिछले महीने बीजेपी सरकार ने संसद में स्त्नहक्रश्वतस् एक्ट को खत्म कर दिया और ङ्क्क्ङ्कत क्र्रूङ्कत नाम से एक नया योजना-आधारित कानून लाया। पंवार ने आगे कहा कि दोनों के बीच मूल अंतर यह था कि स्त्नहक्रश्वतस् एक अधिकार-आधारित कानून था, जबकि ङ्क्क्ङ्कत क्र्रूङ्कत एक योजना-आधारित कार्यक्रम है जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, स्त्नहक्रश्वतस् के तहत, रजिस्टर्ड जॉब कार्ड धारकों को 15 दिनों के भीतर काम मांगने का कानूनी अधिकार था। अब ङ्क्क्ङ्कत क्र्रूङ्कत के तहत वह अधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले, पंचायती राज संस्थाओं के पास यह तय करने का अधिकार था कि गांवों में किस तरह का काम किया जाएगा और साल के किसी भी महीने में मजदूर कब रोजगार मांग सकते हैं। पंवार ने कहा, अगर 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता था, तो मजदूर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार था। ये सभी सुरक्षा उपाय हटा दिए गए हैं, जिससे मजदूर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित हो गया है।केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित फंडिंग पैटर्न की आलोचना करते हुए पंवार ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मजदूरी लागत का 100 प्रतिशत वहन करती थी, जबकि राज्य केवल प्रशासनिक खर्चों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने चेतावनी दी, अब 60:40 का फंडिंग रेशियो लागू कर दिया गया है। कमजोर फाइनेंस वाले राज्य डेवलपमेंट के काम शुरू नहीं कर पाएंगे, जिससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए, ऋत्नक्क्रस् के ओडिशा चेयरपर्सन सुदर्शन दास ने आरोप लगाया कि मौजूदा क्क्छ्क्क सरकार ने ङ्क्क्ङ्कत क्रू त योजना लाकर मूल स्त्नहक्रश्वतस् एक्ट की भावना को खत्म कर दिया है, जिससे, जैसा कि उन्होंने दावा किया, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत दिए गए काम के अधिकार के संवैधानिक मकसद को कमजोर किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्टील लैडल लाइनिंग के जीवनकाल में नया रिकॉर्ड दर्ज

राउरकेला १२/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (एसएमएस-2) के स्टील लैडल संख्या 29 में 210 हीट्स की उल्लेखनीय लैडल जीवनकाल उपलब्धि हासिल कर 150 टन स्टील लैडल की लाइनिंग के जीवनकाल में नया मानक स्थापित किया है। यह उपलब्धि सितंबर 2020 में स्थापित 206 हीट्स के पूर्व रिकॉर्ड से अधिक है।

यह मील का पत्थर रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग (सेवाएँ) विभाग एवं एसएमएस-2 के कर्मचारियों की प्रभावी टीमवर्क, सतत प्रयासों और पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। साथ ही, यह आरएसपी में लैडल रिफ्रैक्टरी प्रदर्शन, परिचालन अनुशासन तथा रखरखाव प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार को भी रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि स्टील लैडल प्रबंधन सेट की आपूर्ति मेसर्स आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया रिफ्रैक्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा की गई थी। उक्त लैडल की लाइनिंग 15 अक्टूबर 2025 को की गई थी और 11 जनवरी 2026 को प्रचालन से उतारे जाने से पहले इसने सफलतापूर्वक 210 हीट्स पूरे किए।

लैडल की बढ़ी हुई आयु अनुकूलित रिफ्रैक्टरी चयन, टैपिंग एवं टीमिंग के दौरान मानक परिचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन, प्रभावी स्लैग नियंत्रण पद्धतियाँ, बेहतर तापमान प्रबंधन, समयबद्ध रखरखाव हस्तक्षेप तथा परिचालन, रिफ्रैक्टरी और रखरखाव विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से प्राप्त की गई इतनी उच्च लैडल लाइफ की उपलब्धि से रिफ्रैक्टरी खपत में कमी, लैडल की उपलब्धता में वृद्धि, परिचालन डाउनटाइम में कमी और सुरक्षा में सुधार हुआ है, जिससे आरएसपी में इस्पात निर्माण कार्यों की विश्वसनीयता और लागत दक्षता में उल्लेखनीय योगदान मिला है।

नालको ने 30,000 करोड़ के निवेश से अंगुल स्मेल्टर और नए थर्मल पावर प्लांट के विस्तार की योजना बनाई

भुवनेश्वर १२/०३ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विज़न में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और नेट-ज़ीरो एमिशन को मुख्य प्रायोरिटी के तौर पर हासिल करने पर ज़ोर दिया गया है, नालको के छ्स्ब्ध बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस विज़न के हिसाब से, हम 0.5 मिलियन टन के एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं और ग्रीन पावर को अपनाने के बारे में भी सोच रहे हैं।

एल्युमिनियम की बड़ी कंपनी ह्रस्ष्ह के चीफ ने यहां ह्वह्रस् को बताया कि उनके 2030 प्लान के हिस्से के तौर पर, हम 30,000 करोड़ रुपये के एक्सपेंशन का प्रपोज़ल दे रहे हैं, जिसमें 0.5 मिलियन टन का स्मेल्टर और 1,080 स्र्ड्ड का थर्मल पावर प्लांट शामिल है। ये दो बड़ी यूनिट हैं जिनकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, DPR की तैयारी शुरू हो चुकी है, और छ्क्क्र तैयार करने वाले कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट इसी महीने पूरा होने की उम्मीद है। हमारा मकसद इस साल जुलाई या अगस्त तक छ्क्क्र के लिए बोर्ड से मंज़ूरी लेना है। घरेलू मार्केट में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए, नालको ओडिशा में अपने अंगुल स्मेल्टर में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के ज़रिए अपनी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग कैपेसिटी को 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना चाहता है। कंपनी ने एक नए 0.5 मिलियन टन एल्युमिनियम स्मेल्टर और 1,080 स्र्ड्ड पावर प्लांट के लिए ऋद्य 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की तैयारी की है। प्रोजेक्ट के 2030 में पूरा होने की उम्मीद है प्रस्तावित एक्सपेंशन में ग्लोबल बेंचमार्क के साथ बेस्ट-इन-क्लास, पर्यावरण के अनुकूल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके 2030 में पूरा होने की उम्मीद है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ह्रस्ष्ह के तीन साल के विज़न के बारे में पूछे जाने पर, सिंह ने कहा कि पहली प्राथमिकता एल्युमिना प्लांट के पांचवें स्ट्रीम एक्सपेंशन को चालू करना है, साथ ही पोट्टांगी माइंस में ऑपरेशन शुरू करना है।

उन्होंने ह्वह्रस् को बताया, यह हमारा पहला टारगेट है। हम इस साल जून में पांचवीं स्ट्रीम के लिए कमीशनिंग प्रोसेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, और पोट्टांगी माइंस में ऑपरेशन भी जून में शुरू होने वाले हैं। डाउनस्ट्रीम और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में, हम 60,000 टन कैपेसिटी वाली एक वायर रॉड मिल लगाने का प्लान बना रहे हैं। एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि ह्रस्ष्ह को अपने प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिटर्स वेदांता और हिंडाल्को पर एक फायदा है क्योंकि उसके पास अपनी बॉक्साइट और कोयला माइंस हैं जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करती हैं और बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज मिलता है।

भुवनेश्वर आश्रम में अनाथ महिला से शादी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिलाई प्रेरणा

भुवनेश्वर १२/०३ (संवाददाता): कभी अकेली और अपनी पहचान की तलाश में भटकने वाली संतोषिनी नायक को आज एक नया परिवार और जीवन भर का साथी मिल गया है। करीब एक दशक पहले मंचेश्वर की सड़कों पर अकेली छोड़ दी गई संतोषिनी नायक ने एक दिल को छू लेने वाली सेरेमनी में शादी की, जिससे उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। सूत्रों के अनुसार, शादी भुवनेश्वर के जीवनज्योति आश्रम में पूरे रीति-रिवाजों और धूमधाम से हुई, जहाँ संतोषिनी अपने रिश्तेदारों द्वारा छोड़े जाने के बाद पली-बढ़ी थीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर खिरोद पटनायक ने उनका हाथ थामा और उनके जीवन साथी बने, जो जिम्मेदारी और करुणा की एक मिसाल है। संतोषिनी ने 12 साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और बाद में उनके मामा के रिश्तेदारों ने उन्हें पढ़ाई के बहाने छोड़ दिया था। तब से जीवनज्योति आश्रम ही उनका घर और परिवार बन गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने ओडिशा में बसने से पहले हैदराबाद के एक होटल में काम किया था। आश्रम के अधिकारियों ने शादी का भव्य आयोजन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कभी भी अनाथ जैसा महसूस न हो। गहनों और कपड़ों से लेकर शादी की पूरी दावत तक, हर रस्म प्यार और सम्मान के साथ निभाई गई। गाँव वालों, शुभचिंतकों और आश्रम के सदस्यों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी और खुशहाल जीवन की कामना की।नई दुल्हन संतोषिनी ने ह्ज्ञ्ङ्क को बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में होगी और मुझे इतना अच्छा परिवार मिलेगा।

पुलिस ने बड़ी गांजा तस्करी का किया पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

संबलपुर १२/०३ (संवाददाता):ओडिशा के संबलपुर ज़िले में चेकिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक कार, 1 लाख रुपये कैश और पांच मोबाइल फोन के साथ 25 किलो 400 ग्राम गांजा ज़ब्त किया है। यह ज़ब्ती रविवार को जमनकिरा पुलिस ने बदरामा के पास की। पुलिस के मुताबिक, रूटीन गाड़ी चेकिंग के दौरान रोकी गई एक कार से यह नशीला पदार्थ बरामद किया गया। गांजे के साथ, अधिकारियों ने 1 लाख रुपये कैश और पांच मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए। ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है।ॱद्यह्यश्व ऋद्गड्डस्र - श्वष्ठ छापेमारी के बाद गंजम में अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया बाद में दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कुचिंडा सब-डिविज़नल पुलिस अधिकारी (स्ष्ठक्क) प्रदीप कुमार दास ने कहा कि गांजे को अवैध रूप से संबलपुर से कोलकाता ले जाया जा रहा था। इस तस्करी रैकेट में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान रोशन सिंह, दीपक पांडे, मोहम्मद दानिश और उज़्म बगारती के रूप में हुई है। ये सभी संबलपुर ज़िले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

स्ष्ठक्क ने कहा, हमें टिप मिली थी कि एक होंडा सिटी कार में गांजा ले जाया जा रहा है और वह संबलपुर की ओर जा रही थी। कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने गाड़ी को रोका, और पूरी तलाशी के बाद, टीम ने भारी मात्रा में गांजा ज़ब्त किया।卐 स्ष्ठक्क ने आगे बताया, एक स्थानीय मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद ज़ब्ती और गिरफ्तारियां हुईं। गांजा दो बड़े बोरों से बरामद किया गया और बाद में ज़ब्त कर लिया गया। कुल 25 किलो 400 ग्राम गांजा ज़ब्त किया गया है। इसके अलावा, 500 रुपये के नोटों में 1 लाख रुपये कैश भी ज़ब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पांच मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए हैं।

आरएसपी में पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी की गई आयोजित

राउरकेला १२/०३ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के सीपीटीआई में एक पूर्व-सेवानिवृत्ति कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (उपकरण एवं स्वचालन), श्री के के सेनगुप्ता उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। महाप्रबंधक प्रभारी (रोल शॉप), श्री एस आर मोहंती सम्मानित अतिथि थे। एक कार्यपालक सहित संयंत्र के 46 कर्मचारी, जो जनवरी 2026 के महीने में सेवानिवृत्त होंगे, सत्र में भाग लिया। %रोशनी% के सत्रों में एक सहज सेवानिवृत्ति के बाद की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ज़रूरी कई तरह के टॉपिक शामिल थे। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा), डॉ. शिवलकर ने निम्नलिखित सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और स्वस्थ सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए रणनीतियों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक (सी एंड आईटी), श्री वी पी आर्य द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदे बताए गए और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति की रक्षा करने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई।वित्त पर सत्र में उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), श्री डी के दाश ने बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं पर विचार किया। सहायक महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में बात की। बदलाव के इस अहम दौर से निपटने और मकसद भरी और एक्टिव ज़िंदगी जीने के लिए महाप्रबंधक प्रभारी (एसपीपी), डॉ. पी के पाढ़ी ने पॉज़िटिव माइंडसेट की तैयारी पर बात की। संगठन के अंदर क्वार्टर वेकेशन और प्रतिधारण नीतियों के विवरण उप प्रबंधक (टाउन सर्विसेज़), श्री भरत महंता द्वारा चर्चा की गई। सेल मेडिक्लेम योजना को सहायक महाप्रबंधक (एचआर-ईए, जी, ईआर और सी), श्री अविनाश द्वारा संबोधित किया गया था .

शुरुआत में सहायक प्रबंधक (एचआर-ईआर एंड सी), श्री एस पी माँझी ने सभा का स्वागत किया जबकि श्री अविनाश ने उप प्रबंधक (एचआर-ईआर एंड सी), श्री एस के नायक, श्रम निरीक्षक, श्री के के परिडा और एचआर-ईआर टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को गले लगाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है।